## TEXTILE INDUSTRY

According to the Committee, as major problem of textile industry arises from fluctuations in output and prices of raw cotton and neither control on ceiling nor support price of cotton has worked successfully. Although Cotton Corporation of India was set up with a view to stabilising prices of cotton through effective intervention in cotton market, it has never been provided the necessary fund with which to achieve the above objectives. The Committee, therefore, recommends that Cotton Corporation of India should be freed from bureaucratic control, given necessary funds and general guideline and authorised to buy 30 per cent of the cotton crop and also build up a buffer stock. The Committee further recommends that control on weaving capacity of mill sector should continue; price stamping of mill cloth withdrawn except on janata cloth and reservation of spare production by handloom should be enlarged.

## COAL

The Committee recommends that price of coal should be determined by an independent authority with a view to discouraging its imprudent use.

#### STEEL

The tight administrative control over steel prices should be relaxed. There should be no licensing control in respect of cement expansion and a special allowance of at least Rs. 20 per tonne of cement should be allowed to producers. To the extent controls are considered necessary on cement prices, distribution, etc., the same may be exercised under Essental Commodities Act instead of Industrial Development and Regulation Act.

The Committee recommends amendment of Gold Control and total prohibition on manufacture of gold ornaments above 19 carate purity. To meet demand for 18 carate gold, the Committee wants Government to import gold. It also suggests revival of gold bonds with suitable modifications.

The Committee feels that there is a need for a separate list of reserved items for decentralised sector, especially for artisans and cottage industry type workers. This list will include all dhotics and sarees with border, all carpet weaving, shawls, blankets, etc. The Committee further recommends, that there should be separate list for Government and public sector purchases exclusively from cottage and village industries.

## **CREDIT CONTROL**

In regard to credit control, the Committee recommends steps to make available adequate credit speedily to small producers at reasonable commercial rates of interest. It recommends that so per cent of the additional credit should be deployed to decentralised sector.

The Committee feels that controls, particularly on price without an adequate machinery for distribution, leakages in distribution system, rent control, etc., are the main sources of black money. To check the expansion of black money, the Committee recommends that to the extent possible other alternative policies like buffer stock operations and fiscal policy should be used. There is need for a small list for restricted items involving individual discretion.

The Committee recommends that at the national level all controls and subsidies should be monitored in Planning Commission by a monitoring unit to be set up, so that required adjustments could be made from time to time. Similar monitoring of controls should be undertaken by State Planning Boards. The Committee further recommends that monitoring of prices and distribution control should be made easier and should be made more efficient by organising citizen councils in each area and also by involving organisations like chambers of commerce and industry for undertaking voluntary regulation of the conduct of their members.

## राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों हारा किसानों को विए गए प्रजी की वसूती '

767. भी बचा राज झाक्य : क्या उप प्रधान मंत्री तथा चित्त मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैकों तथा भूमि विकास बैंको द्वारा किसानों को सिंचाई प्रयोजनों के लिए दिये गये ऋष्ण उन से 9 वर्ष के भीतर बसूल किये जाते हैं जीर उस राशि पर चक्कवर्ती व्याज वसूल किया जाता है तथा किसानों से पहली अयवा दूसरी किस्त चसूल करने के बाद भी उनसे मूलप्रन पर लगातार 9 वर्ष का चक्रवर्ती व्याज बसूल किया जाता है ; 3

(ख).स्या जिन डेरियों के लिए मूटन दिया जाता है उनसे सरकारी एजेन्सियां दूस खरीवती हैं घौर दूस की किस्म का निक्षत्र कर्मचारियों द्वारा प्रपने स्वाविके द्वारा किया जाता है तथा इस किस्म के माधार पर किसानों को उनके दूधका जुन्म प्रथा किया जाता है जिसके फलक्षत्रका किसान वही यूनिकन से ज्या पर केवल स्वाज ही प्रथा कर पाठे हैं तथा अपना' गुजारा थी नहीं कर पाठे हैं; जीर (ग) क्या सरकार का विचार इन लोगो की समस्याओं को हुल करने के लिए झावस्यक कदम सठानी का है ?

विच मंत्रालय में राज्य मंत्री (थी जुल्फिसार खल्लाह ) : (क) इवि पुनर्वित्त और विकास नियम (ए० आर० डी० सी०) की छोटी सिचाई के प्रयोजमों विषयक बोजना के प्रधीन ऋण वापसी की अवधि ऋणकर्त्ता की सदायगी की क्षमता सौर ऋण से प्राप्त होने वाली सम्पत्तियो के जीवनकाल की अवधि के आधार पर तय की जाती है। पम्प-सैटों की खरीद के लिए यह प्रवधि 7 वर्ष होती है जब कि दूसरे छोटे सिंचाई के पूजी निवेशों जैसे कुझो आदि के लिए जहण वापसी की अधिकतम अवधि 9 वर्ष होती है , साय ही छोटे किसान इस प्रकार के ऋण 15 वर्ष तक की अवधि के लिए ले सकते हैं। वाणिज्यिक बैंक कृषि ऋणों की किम्न की वापसी भवायगी के समय व्याज लेते हैं भौर मौजूदा देव राशियो पर चक्रवर्ती व्याज नहीं लेते । भलबत्ता जब इस तरह के सावधिक ऋणों की किस्त अति देय (भोबरड्यू) हो जाती है तो चक्रवर्ती ब्याज बसूल किया जाता है।

(ख) भौर ('ग). साधारणत एक **आ**ंग्रतः सम्बद्ध व्यवस्था होती है, जिसमें सार्वजनिक या सहकारी क्षेत्र से संगठत हार्ड व्यवस्था उपलब्ध होने पर ऋणकर्ताभो से यह मनेका को जाती है कि वे प्रपत्नी उपज सम्बद्ध सगठनो की मार्फत बेचे भीर वे सगठन ऋणकर्ताभो को देय राधियो को उपज की बिको मे से वसूल कर ले । डेरी फार्म वालो को इस प्रकार बेचे गये हुध पर, उनके दूध में चिकनाई के प्राधार पर दूध की मात्रा के प्रनुसार प्रदायगी की जाती है । जहा कही इस तरह की हाई व्यवस्था उपलब्ध नही है मीर ऋणकर्ता ध्रे मही राये सोसाइटी का स्टाफ किस्तें वसूल करता है कीर राज्य सरकार के प्राधानपियो की भी मदद ली जाती है ।

जिला स्तर पर, जिला स्तरीय समिति धौर राज्य स्तर पर, राज्य स्तरीय समन्वम समिति से धाशा की जाती है कि वे समय-समय पर होने वाली धपनी बैठको में विलीय धाणिकरणो के बीच विभिन्न राज्य-कार्यक्रमो के कार्यान्वयन का समन्वय करे भीर इन बैठकों मे योजनाघो के कार्यवालन में धाने वाली समस्याघो धौर कठिनाईयो को दूर करने की दुष्टि से बचा थी की जा सकनी है।

# आंझ प्रदेश तथा तमिलनाबु में लमुडी तुफान की सूचना

769. भी राजेम्ड कुमार शर्मा : क्या पर्यटन भीर सागर विस्तानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आघ्र प्रदेश तथा तमिल-साडू में हास ही में आये समुद्री तूरुान के बारे में पूर्व सूचना प्राप्त वी जीर क्या सरकार इसके वावजूव भी इन स्थानों घर सुरक्षा के उचित उपाय नहीं कर सकी;

(क) अदि हो, हो इसके क्या कारण हैं; सीप

(ग) क्या इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटल और नानर विमानन वंधी (धी प्रायोसन कौसिक) : (क) जारत नौसम विज्ञान विभाग ने 12-5-79 को प्रांधा प्रदेश में माए दक्षिण तटवर्ती सपुढी तूफान के बारे में 48 घण्टे पहले चेतावनी जारी कर दी थी। प्रेस रिपोर्टी के प्रमुसार राज्य सरकार ने सेना की सहायता से प्रभावित सेतों से लोगों को निकालने के लिए पहले ही मौर तुरना ऐसी कार्यवाही सुक कर दी थी जिससे बडे पैमाने पर लोगों की जान बचाई जा सकी।

(ख) मौर (ग) सुरक्षा प्रबन्धो की व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

#### Recruitment of qualified Harijan Engineers in Government under takings

770 SHRI SHIV NARAIN SARSONIA: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state whether there is any proposal to absorb qualified Harijan Engineers, Mechanical, Givil and Electrical by recruiting them for our Government Undertakinga and construction projects abroad?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): Government's order on reservation of posts for candidates belonging to SC/ST have been extended to the Central Public Undertakings However, there is no proposal to recruit candidates belonging to these categories specially for construction projects abroad of public sector enterprises.

## Cases of Violation of cermin Acts Regissered against Forsigners

771 SHRI DALPAT SINGH PARASTE: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state the number of cases under the Dangerous Druga Act and the Violation of Foreign Exchange Regulation Act that have been registered against foreigners during the last six months?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SH RI SATISH AGARWAL): Information is being collected and will be laid on the Table of the House. 1